

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने [प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण](#) के तहत तीन लाख परिवारों के लिये प्रथम कसित के रूप में 1,200 करोड़ रुपए की सहायता राश्ट्रांसफर की।

मुख्य बढि

- इन लाभार्थियों को अगले सौ दिनों में दूसरी एवं तीसरी कसित के रूप में और 80 हजार रुपए दिये जाएंगे।
- इसके अलावा, [मनरेगा](#) के माध्यम से 90 दिनों के अकुशल मज़दूरी के रूप में 22,050 और [लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान](#) से शौचालय निर्माण के लिये 12 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G):

- **शुभारंभ:** वर्ष 2022 तक “सभी के लिये आवास” के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये, पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना [इंदिरा आवास योजना \(IAY\)](#) को 1 अप्रैल 2016 से [केंद्र प्रायोजित योजना](#) के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) में पुनर्गठित किया गया।
- **शामलि मंत्रालय:** ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- **स्थिति:** राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने [लाभार्थियों को 2.85 करोड़ घर स्वीकृत किये हैं](#) और मार्च 2023 तक 2.22 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं।
- **उद्देश्य:** मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवारों, जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं, को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना।
- **गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line- BPL)** जीवन यापन करने वाले ग्रामीण लोगों को आवास इकाइयों के निर्माण तथा मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना।
- **लाभार्थी:** [अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति](#), मुक्त बंधुआ मज़दूर और गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विरग के लोग, युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों की वधियाँ या उनके नकिट संबंधी, पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, वकिलांग व्यक्ती तथा [अल्पसंख्यक](#)।
- **लाभार्थियों का चयन:** तीन-चरणीय सत्यापन जैसे [सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011](#), [ग्राम सभा](#) और [जियो-टैगिंग](#) के माध्यम से।
- **लागत साझाकरण:** मैदानी क्षेत्रों के मामले में केंद्र और राज्य 60:40 के अनुपात में व्यय साझा करते हैं तथा [पूर्वोत्तर राज्यों](#), दो हिमालयी राज्यों एवं जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मामले में **90:10 के अनुपात** में व्यय साझा करते हैं।
- **केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख सहित अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में केंद्र 100% लागत वहन करता है।**